

प्रेषक,

कै० आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 24 अक्टूबर, 2017

विषय:- रमसा के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा योजना (IEDSS) के अनावर्तक मदों में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक: अर्थ-1/19605/5क-1/(09)/2017-18, दिनांक: 29 सितम्बर, 2017 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा योजना (Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage) के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश सं०: 791/XXIV-3/17/02(66) 2011 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश रू० 17.57 लाख के सापेक्ष राज्यांश रू० 1.95 लाख की धनराशि संलग्न परिशिष्ट-‘अ’ की तालिका के अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षकों की मानक मदों में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों/शर्तों के आलोक में शासन के वर्तमान वित्तीय व प्रशासकीय नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। निर्माण कार्यों के संबंध में विस्तृत आगणनों का सक्षम/निर्धारित स्तर से परीक्षण कराकर तकनीकी व वित्तीय अनुमोदनोपरांत ही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत नियमों की अनुपालन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित की जाय तथा कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर लिया जाएगा।

2. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुयल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

3. उक्त व्यय मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों के शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 2047/XIV-219(2006), दिनांक: 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

5. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों/शर्तों के आलोक में शासन के वर्तमान वित्तीय व प्रशासकीय नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण कर धनराशि राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. उक्त स्वीकृत धनराशि भारत सरकार के उपरोक्त पत्र में प्रदत्त निर्देशानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत कुल धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुरूप अनुमन्य मदों पर किया जायेगा।



8. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक: 30 जून, 2 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. प्रत्येक कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 475/XXVII(7)/2008, दिनांक: 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जायेगा तथा उक्तानुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराते हुए शत-प्रतिशत भौतिक प्रगति आख्या शासन को समयबद्ध ढंग से अवश्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

10. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मददेनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

11. स्वीकृत की जाने वाली धनराशि से आंगणन में प्राविधानित समस्त कार्यों को पूर्ण किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

2— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11, 30 एवं 31 के आयोजनागत के अधीन लेखाशीर्षक 2202- शिक्षा ,खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 02- सामान्य शिक्षा, 202- माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संलग्नक परिशिष्ट-‘अ’ में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:96(म0)/XXVII(3)/2017-18, दिनांक: 06 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 1333 /XXIV-3/17/02(66)2011, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- अनु सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

3- राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।

6- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।

7- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं 23- लक्ष्मी रोड, देहरादून।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
महिमा
(महिमा)
उप सचिव।
५

शासनादेश संख्या: 1333 /XXIV-3/17/02(66)2011, दिनांक: 24 नवम्बर, 2017 का संलग्नक:-

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	(रूपये लाख में) केन्द्रांश
1.	11	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 0103-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA 90 प्रति.के.स.)	20-सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता	1.34
2.	30	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 0101-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	20-सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता	0.47
3.	31	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 800-अन्य व्यय 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 0101-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	20-सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता	0.14
	योग			1.95

(राज्यांश रुपये एक लाख पन्चानवे हजार मात्र)

h' h'
(महिमा)
उप सचिव।